



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154 ]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, अप्रैल 25, 1996/वैशाख 5, 1918.

No. 154]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 1996/VAISAKHA 5, 1918

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1996

आयकर

सा. का. नि. 189( अ ).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद-30 के पैराग्राफ-1 के अनुसार संविदाकारी राज्यों द्वारा अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने के पश्चात् दिनांक 23-11-1995 को प्रवृत्त हो गया है।

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबन्ध

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार

और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

इटली गणराज्य की सरकार

के बीच अभिसमय।

भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपव्ययन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

## अध्याय - I

### अभिसमय का क्षेत्र

#### अनुच्छेद 1

#### वैयक्तिक कार्य क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों संधिदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं ।

#### अनुच्छेद 2

#### अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

जिन करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे निम्न प्रकार से हैं :-

§क§ भारत के मामले में :

1. आयकर जिस पर लगाया गया कोई अधिभार भी शामिल है; तथा
2. अतिकर ;

§जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा § :

§ख§ इटली के मामले में ;

1. वैयक्तिक आयकर ;
2. निगमित आयकर ; और
3. स्थानीय आयकर ;

भले ही इन करों को स्रोत पर विधारण करों द्वारा वसूल किया जाता है ।

§ जिन्हें इसके बाद "इटैलियन कर" कहा जाएगा § ।

2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा मौजूदा अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् इसी अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अंतर्गत अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे ।

प्रत्येक वर्ष के अन्त में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी परिवर्तनों के संबंध में, जो उनके अपने-अपने करायान कानूनों में किए गए हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं, एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे तथा संगत अधिनियमों एवं विनियमनों की प्रतियां भेजेंगे ।

## अध्याय - II

### परिभाषाएं

#### अनुच्छेद 3

#### सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

§क§ "भारत" शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें शामिल है - राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उनके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;

§ख§ "इटली" शब्द से अभिप्रेत है - इटली गणराज्य जिसमें यह भी शामिल है - इटली का राज्यक्षेत्रीय जल तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र तथा उक्त राज्यक्षेत्रीय जल से परे कोई भी क्षेत्र, विशेषकर प्रायदीप के क्षेत्राधिकार से संलग्न समुद्रतल तथा अवमृदा और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण एवं समुपयोजन सम्बन्धी इटैलियन कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत राज्यक्षेत्रीय जलों से परे स्थित इटैलियन दीपसमूह ;

§ग§ "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा इटली अभिप्रेत है ;

§घ§ "कर" शब्द से विषयगत; पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा इटैलियन कर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए किसी अर्थवण्ड को निरूपित करते हैं ;

§ड. § "व्यक्ति" शब्द से वही अर्थ अभिप्रेत है जो सम्बन्धित संविदाकारी राज्यों में लागू करायान कानूनों में है ;

§च. § "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कर कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;

§छ. § "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

§ज. § भारतीय कर के संबंध में "वित्तीय वर्ष" शब्द से "पिछला वर्ष" अभिप्रेत है जैसाकि आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ में परिभाषित है ;

§श. § "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन, जो किसी उद्यम द्वारा संचालित हो जिसका एक संविदाकारी राज्य में अपना वास्तविक प्रबन्ध-स्थान है, सिवाय उस स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

§भ. § "राष्ट्रक" शब्द से अभिप्रेत है - किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त कोई व्यक्ति और उस संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से अपने हैसियत प्राप्त करने वाला कोई विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा संस्था:

§ट. § "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है - भारत में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय §राजस्व विभाग§ अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि, और इटली के मामले में वित्त मंत्रालय ।

2. जहां तक दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवधानों के प्रवर्तन का संबंध है, किसी पद का, जो इसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक विषयगत पठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा, जो उस राज्य में प्रवृत्त कानूनों के अंतर्गत उन कर्तों से संबंधित है, जो इस अभिसमय के विषय हैं ।

## अनुच्छेद 4

## राजस्व संबंधी अधिवास

1. इस अधिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, जो उस राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार उस राज्य का निवासी है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी आवासीय हैसियत इस अधिसमय के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियमों के अनुसार तय की जाएगी :

॥क॥ उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसे स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो। यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं ॥जिसे इसके बाद "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" कहा जाएगा॥;

॥ख॥ यदि संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निर्धारण नहीं किया जा सकता है अथवा यदि उसके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा, जिसमें वह आदतन रहता हो;

॥ग॥ यदि वह दोनों ही संविदाकारी राज्यों में आदतन रहता हो अथवा उनमें किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;

॥घ॥ यदि वह दोनों ही संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

## अनुच्छेद 5

## स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहां उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

॥क॥ प्रबन्ध-व्यवस्था का कोई स्थान;

॥ख॥ कोई शाखा;

॥ग॥ कोई कार्यालय;

॥घ॥ कोई कारखाना;

॥ङ॥ कोई कार्यशाला;

॥च॥ कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

॥छ॥ कोई भण्डारगार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो;

॥ज॥ कोई परिसर जिसका उपयोग विक्रय स्थल अथवा आदेशों को प्राप्त करने अथवा मंगाने के लिए किया जाता हो;

॥झ॥ कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा समुपयोजन के लिए किया जाता हो;

॥ञ॥ कोई भवन स्थल, कोई निर्माण कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा असेम्बली परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यक्रम जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यक्रम ॥अन्य ऐसे स्थलों, परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों सहित, यदि कोई है॥ 6 माह से अधिक की अवधि के लिए जारी रहते हैं जहां ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यक्रम जो मशीनरी अथवा उपकरण की बिक्री के लिए प्रासंगिक है, छः महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी रहते हैं और परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यक्रम के लिए अदा करने योग्य प्रकार मशीनरी और उपकरण के बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हों।

बशर्ते कि इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन का होना तथा उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाना समझा जाएगा, यदि उस राज्य में खनिज तेलों के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन में प्रयुक्त हुए अथवा प्रयुक्त करने के लिए किराए पर लिए संयन्त्र और मशीनरी के संबंध में अथवा उसकी आपूर्ति के लिए सेवाओं अथवा सुविधाओं की व्यवस्था करता है।

इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- §क§ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का उपयोग;
- §ख§ केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- §ग§ किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- §घ§ उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा उसके लिए सूचना पत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- §ङ·§ उद्यम के लिए अनन्यरूप से विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिए अथवा समरूप कार्यकलापों के लिए, जिनका स्वरूप प्रारम्भिक अथवा उपसंगी हो, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ।

तथापि, उप पैराग्राफ §क§ से §ङ·§ तक के उपबन्ध उस उद्यम पर लागू नहीं होंगे, जहां वह उद्यम उक्त उप-पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार का कोई अन्य निश्चित स्थान रखता है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता से भिन्न, जिसपर पैराग्राफ 5 लागू होता है, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, वहां उस उद्यम को प्रथमोल्लिखित राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का स्वामी होना समझा जाएगा, यदि :

- §क§ उसे उक्त उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का कोई प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस राज्य में प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उस व्यक्ति के कार्यकलाप उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदने तक सीमित नहीं हो;
- §ख§ उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में माल का अथवा पण्य-वस्तुओं का आदतन कोई स्टॉक रखता है, जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो;

अथवा

- §ग§ वह, प्रथमोल्लिखित राज्य में समग्रतः अथवा लगभग समग्रतः स्वयं उद्यम के लिए अथवा उस उद्यम के लिए तथा अन्य उद्यम के लिए जो उस उद्यम की नियन्त्रित करता हो, उसके द्वारा नियन्त्रित होता हो अथवा उसी प्रकार के सामान्य नियन्त्रण के अधीन

हो, व्यावहारिक रूप से आदेश प्राप्त करता हो;

§घ§ इस प्रकार के कार्य में, वह उद्यम के लिए उद्यम का माल अथवा फण्य-वस्तुओं का उस राज्य में निर्माण करता है अथवा उन्हें संसाधित करता है ।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्वामित्व में दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण किसी स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । लेकिन, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किए जाते हों, जो उस उद्यम को नियन्त्रित करता हो, उस उद्यम द्वारा नियन्त्रित हो अथवा उसी प्रकार के सामान्य नियन्त्रण के अधीन हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

6. यदि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियन्त्रित करती है अथवा उससे नियन्त्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य §चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा§ में कारोबार करती है तो इस तथ्य से उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी अपने आप में दूसरी कम्पनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं मानी जाएगी ।

### अध्याय - III

#### आय का करधान

#### अनुच्छेद 6

#### अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति §जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है§ से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी वशा में ये शामिल होंगे - अचल



सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हैं, अथवा सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कार्य-संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार को भी "अचल सम्पत्ति" के रूप में समझा जाएगा। जलयान, नौकाएं तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

### अनुच्छेद 7

#### व्यापारिक सभ्य

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लक्ष्यों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लक्ष्यों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा, जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता है :

॥क॥ उस स्थायी संस्थापन;

॥ख॥ उस दूसरे राज्य में एक-समान अथवा उससे मिलते-जुलते माल अथवा पण्य-वस्तुओं की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेची जाती है; अथवा

॥ग॥ उस दूसरे राज्य में कारोबार सम्बन्धी किए जाने वाले एक-समान अन्य कार्य-कलाप अथवा उससे मिलते-जुलते कार्यकलाप, जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हैं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लक्ष्यों को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और निम्न उद्यम होता और उस उद्यम के स्वरूप पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है। किसी भी हालत में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण लाभों

की सही राशि का निर्धारण करना असम्भव है अथवा उसके निर्धारण में असाधारण कठिनाइयाँ आती हैं वहाँ उक्त स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का अनुमान एक उचित आधार पर लगाया जाए ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन व्ययों पर कटौतियों के रूप में अनुमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हों, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों, जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों ।

4. कोई भी लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा, कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए, जो कि स्थायी संस्थापन है, निर्यात के प्रयोजनार्थ माल अथवा फसल-वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

6. जहाँ लाभों में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे ।

### अनुच्छेद 8

#### वायुयान परिवहन

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान के परिचालन से प्राप्त आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी मूल किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ :

§क§ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिचालन से सम्बन्धित निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयान के परिचालन से प्राप्त आय माना जाएगा; और

§ख§ "वायुयान परिचालन" से तात्पर्य होगा - वायुयान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा अवक्रेताओं द्वारा वायुयान से व्यक्तियों, पशुधन, डाक अथवा माल के परिवहन का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित कोई अन्य कार्यकलाप शामिल हैं ।

## अनुच्छेद 9

## जहाजरानी

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से किसी सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की आय उसी राज्य में ही कराधेय होगी ।
2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी पूल, जलयानों के प्रचालन में रत किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन फर्जेसी के किसी संयुक्त कारोबार में भाग लेने से प्राप्त होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे ।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के प्रचालन से संबंधित नियमों पर ब्याज को ऐसे जलयानों के प्रचालन से प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबन्ध ऐसे ब्याज पर लागू नहीं होंगे ।
4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के प्रचालन से प्राप्त आय में निम्नलिखित शामिल होंगे :
  - ॥क॥ ऐसे जलयानों के पूर्णतः अथवा फ़कल नाव के आधार पर किराए से प्राप्त लाभ, यदि ऐसे किराए के लाभ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से प्रासंगिक होते हों; और
  - ॥ख॥ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा फ़ण्य-वस्तुओं के परिवहन के संबंध में केन्टेनरों ॥जिनमें केन्टेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा तत्सम्बन्धी उपकरण भी शामिल हैं॥ के इस्तेमाल, अनुरक्षण अथवा किराए से प्राप्त लाभ ।
5. पैराग्राफ 1 तटीय यातायात के परिणामों से उत्पन्न लाभों पर लागू नहीं होगा ।

## अनुच्छेद 10

## सहयोगी उद्यम

जहां :

- ॥क॥ एक सौविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सौविदाकारी राज्य की प्रबन्ध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- ॥ख॥ वे ही व्यक्ति एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबन्ध-व्यवस्था नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं; और दोनों मामलों में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जैसे कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी

लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी भी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

### अनुच्छेद 11

#### लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में करावीय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

§क§ लाभांश की सकल राशि का 15 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी ऐसी कम्पनी है, जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत शेयर रखती है;

§ख§ अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का 25 प्रतिशत ।

इस पैराग्राफ का उक्त लाभों के सम्बन्ध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है ।

3. पैराग्राफ 2 §क§ के उपबन्ध इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किए गए निवेश से उत्पन्न हुए लाभांशों पर लागू होंगे ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों "जोइसेस" अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापकों के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों, जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों में भागीदारीता से प्राप्त आय के साथ-साथ अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय से भी है, जिस पर शेयरों से प्राप्त आय पर उस राज्य के कर कानूनों द्वारा लगाए जाने वाले करों के अनुसार ही कर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उक्त दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है, और जिस सम्पत्ति के संबंध में

लाभान्शों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके अपने कानूनों के अनुसार ऐसे लाभान्श पर कर लगाया जाएगा।

6. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभान्शों पर उस स्थिति में किसी भी प्रकार कर कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभान्श उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जहां तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभान्शों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है, वहां उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ-सम्बन्धी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभान्श अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

## अनुच्छेद 12

### ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य में, उसी राज्य में ऋण अथवा उधार के संबंध में उद्भूत ब्याज पर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों, प्रचार्य कर की राशि ऐसे ब्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के रहते हुए भी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए ब्याज को उस राज्य में कर से छूट मिलेगी यदि :

§क§ ब्याज को अदा करने वाला उक्त संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण हो; अथवा

§ख§ ब्याज किसी ऐसे अभिकरण अथवा करक §इसमें कोई वित्तीय संस्थान भी शामिल है§ को अदा किया जाता है, जिसके संबंध में दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच सहमति हुई हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अभिप्राय यह है - सरकारी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों, चाहे वे रेहन के तहत सुरक्षित हों अथवा नहीं हों और चाहे वे लाभों में भागीदारित्व

का कोई अधिकार रखते हों अथवा नहीं, से प्राप्त आय, और प्रत्येक प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय के साथ-साथ उस राज्य जिसमें आय उद्भूत होती है, के करधान कानूनों के अनुसार धन को उधार देने से प्राप्त आय से सम्बद्ध आय ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का प्राप्तकर्ता, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे सविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज अदा किया गया हो, वहां इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो । ऐसे मामले में, उस दूसरे सविदाकारी राज्य में, उस राज्य के अपने कानूनों के अनुसार ब्याज पर कर लगाया जा सकेगा ।

6. ब्याज किसी सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक अथवा प्रशासनिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज उस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां ब्याज को अदा करने वाले और उसके प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण अदा किए गए ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में ब्याज को अदा करने वाले और उसे प्राप्त करने वाले के बीच सहमति हुई होती, ऐसी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन करते हुए, प्रत्येक सविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

## अनुच्छेद 13

## रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक सौविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस सौविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा । लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टी" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्यों के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें रेडियो अथवा टेलिविजन प्रसारण के सम्बन्ध में उपयोग में आने वाली सिनेमाटोग्राफ फिल्मों अथवा फिल्मों अथवा टेप, कोई पेटेंट, कोई व्यापारिक चिन्ह, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है ।
4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद पर प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के लिए, जिनमें तकनीकी सेवाओं अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिकृता रूप में, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिमाण में की जाने वाली अदायगियों से अभिप्रेत है ।
5. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी है, और दूसरे सौविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा सौविदा के संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, उक्त दूसरे सौविदाकारी राज्य में उसके अपने कानून के अनुसार रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर लगाया जाएगा ।

6. एक सविदाकारी राज्य में रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टी और फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक अथवा प्रशासनिक उप-प्रभाग उस राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, एक सविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है, जो ऐसा संबंध न होने की स्थिति में अदा की गई होती, तो उस स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अंतिम-वर्णित राशि पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों पर सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रत्येक सविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

#### अनुच्छेद 14

#### पुंजीगत अभिलक्षण

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में यथा-उल्लिखित और दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलक्षणों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल-सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलक्षणों पर, जो एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से सम्बन्धित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलक्षणों पर, जो सम्पत्ति एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं को सम्पन्न करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन [अकेले अथवा समग्र उद्यम के साथ] अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलक्षण भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।



3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों या वायुयानों अथवा ऐसे जलयानों और वायुयानों के संचालन से सम्बन्धित चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी सौविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसमें उक्त उद्यम की प्रभावी प्रबन्ध-व्यवस्था का स्थान स्थित है ।
4. किसी ऐसी कम्पनी, जिसकी सम्पत्ति मुख्य रूप से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी सौविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति है, के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगेगा ।
5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित किसी कम्पनी से भिन्न अन्य कम्पनी, जो एक सौविदाकारी राज्य की निवासी है, के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगेगा ।
6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न अन्य सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी सौविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसका अन्तरणकर्त्ता निवासी है ।

### अनुच्छेद 15

#### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय पर उसी राज्य में कर लगेगा । ऐसी आय पर दूसरे सौविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, यदि ऐसी सेवाएं उक्त दूसरे राज्य में निष्पादित की गई हों और यदि :
- ॥क॥ उक्त दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी संगत वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हो; अथवा
- ॥ख॥ उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में कोई नियत स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो परन्तु केवल उतने भाग पर ही कर लगेगा, जो उस नियत स्थान को उद्भूत हुई हो ।
2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद के अर्थ-विस्तार में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन सम्बन्धी कार्यकलापों के साथ-साथ चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

## अनुच्छेद 16

## पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19 और 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक सौविदाकारी के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि वह नियोजन दूसरे राज्य में नहीं किया गया हो। यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सौविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

॥क॥ प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो; और

॥ख॥ पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजन द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है, जो उसे दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

॥ग॥ पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान से वहन नहीं किया गया हो, जो नियोजन का दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान पर सवार होकर उसके परिचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी सौविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसमें उक्त उद्यम की प्रभावी प्रबन्ध-व्यवस्था का स्थान स्थित है।

## अनुच्छेद 17

## निदेशकों की फीस

एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे सौविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की गई निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

## अनुच्छेद 18

## कलाकार तथा खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्त्ता, जैसाकि किसी थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा टेलीविजन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में इस प्रकार की प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबन्धों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें उस मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।
3. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे कार्यकलाप, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की जिसमें उसका राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित हों ।
4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा एक संविदाकारी राज्य में अपनी उसी हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय उक्त मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी स्वयं को प्राप्त नहीं होती हो, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि उक्त दूसरा व्यक्ति उक्त दूसरे राज्य की, जिसमें उसका राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित हो ।

## अनुच्छेद 19

## पेंशन

अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्याधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को विगत में किए गए नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इस प्रकार के मिलते-जुलते अन्य पारिश्रमिक पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगेगा ।

## अनुच्छेद 20

## सरकारी सेवा

1.
  - §क§ किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक अथवा प्रशासनिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा उस राज्य के लिए अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा उसके प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के निमित्त प्रदत्त पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा;
  - §ख§ लेकिन, ऐसे पारिश्रमिक पर, दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में <sup>की</sup> जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :
    - §i§ उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा
    - §ii§ मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं बना था ।
2.
  - §क§ किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक अथवा प्रशासनिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित किए गए कोष द्वारा अथवा उसमें से किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ;
  - §ख§ लेकिन ऐसी पेंशन, केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि वह व्यक्ति उस राज्य का राष्ट्रिक है और निवासी है ।
3.
 

अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19 के उपबन्ध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक अथवा प्रशासनिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के संबंध में की गई सेवाओं के निमित्त प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे ।

## अनुच्छेद 21

## प्रोफेसर अध्यापक और अनुसंधानकर्ता

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक, जो अध्यापन अथवा किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय अथवा सरकार अथवा लाभ-निरपेक्ष किसी संगठन के स्वामित्व के अन्य शैक्षिक संस्थान में अनुसंधान के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य का दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी दौरा करता है तथा जो राज्य का निवासी है अथवा ऐसा दौरा करने के तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी था, तो उस स्थिति में उसे ऐसे अध्यापन अथवा अनुसंधान से प्राप्त पारिश्रमिक पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।
2. यह अनुच्छेद ऐसे अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा अनुसंधान मूलतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

## अनुच्छेद 22

## विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है :-
  - §क§ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में; अथवा
  - §ख§ किसी कारोबार-प्रशिक्षु के रूप में; अथवा
  - §ग§ अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए, किसी सरकार से, धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक अथवा शैक्षणिक संगठन से कोई अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से मुक्त रखा जाएगा :
  - §i§ भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए विदेश से प्राप्त अपने पारिश्रमिक और भेजी गई सभी रकमें;
  - §ii§ अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार पर; और
  - §iii§ उस दूसरे राज्य में समय की किसी ऐसी अवधि के लिए, जो अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित हो, जैसा भी मामला हो, किसी नियोजन के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में।

2. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के कर्मचारी के रूप में अथवा उसके साथ किए गए अनुबन्ध के अधीन अथवा ऐसे उद्यम अथवा संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति से तकनीकी, व्यावसायिक अथवा कारोबार संबंधी अनुभव प्राप्त करने के प्रारम्भिक प्रयोजन के लिए पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी संगठन का दौरा करता है तो उस व्यक्ति को उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी अवधि के लिए किसी नियोजन के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में किसी भी वर्ष में उस सीमा तक ऐसे पारिश्रमिक की राशि से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर-मुक्त रखा जाएगा जो 5,000,000 इटैलियन लिरा अथवा इसके बराबर भारतीय रुपयों से अधिक न हो, जैसा भी मामला हो ।

### अनुच्छेद 23

#### अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों और जिनपर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जाएगा ।

### अध्याय - IV

#### अनुच्छेद 24

#### दोहरे कराधान के अपकरण की पद्धति

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामले में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इस अभिसमय में उनके विपरीत कोई उपबन्ध नहीं किया जाता है ।

2. इस बात पर सहमति है कि दोहरे कराधान का परिहार इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार किया जाएगा :

3. §क§ इटली के कानूनों के अधधीन तथा इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा इटली में रहते हुए स्रोतों से उद्भूत आय के संबंध में, जिस पर भारत

और इटली दोनों ही देशों में कर लगाया जा सकता है, देय इटैलियन कर की राशि पर चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से देय हो अथवा उसकी कटौती की गई हो, ऐसी आय के संबंध में देय भारतीय कर के लिए क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी लेकिन भारतीय कर के अनुपात से अनधिक ऐसी राशि में जो भारतीय कर के लिए प्रभार्य समस्त आय के लिए हो ।

§ख§ उपर्युक्त उप-पैराग्राफ §क§ में उल्लिखित क्रेडिट के प्रयोजनों के लिए, जहां भारत का निवासी कोई ऐसी कम्पनी हो जिसके द्वारा अतिकर देय है, भारतीय कर के प्रति क्रेडिट की दी जानी वाली अनुमति की स्थिति में भारत में उस कम्पनी द्वारा देय आयकर तथा भारत में उस कम्पनी द्वारा देय अतिकर पर अधिशेष, यदि कोई हो, पर प्रथमतः उपर्युक्त क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी ।

§क§ यदि इटली का कोई निवासी आय की ऐसी मदों का स्वामी है जो भारत में कराधेय हैं तो इटली देश इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट आयकरों का निर्धारण करते समय उस आधार को शामिल कर सकता है जिस आधार पर ऐसे कर आय की उक्त मदों पर अभी लगाए जा सकते हैं जब तक कि इस अभिसमय के विशिष्ट उपबन्ध अन्यथा व्यवस्था नहीं करते हों । ऐसे मामले में इटली करों में से आय पर यथा-संगणित भारतीय कर की कटौती करेगी, लेकिन उपर्युक्त इटैलियन कर के अनुपात से अनधिक किसी ऐसी राशि में जो आय की ऐसी मदें समस्त आय के लिए हों । इसके विपरीत उस स्थिति में कोई कटौती प्रदान नहीं की जाएगी यदि आय की मद इटली के कानूनों के अनुसार उक्त आय के प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर इटली में अन्तिम अवधारण कर के अधधीन है ।

§ख§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 और 4 के प्रयोजनों के लिए जहां पर किसी सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले कारोबार के लाभों, लाभान्शों, ब्याज, रायटियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों को उस राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार कर मुक्त रखा जाता है अथवा उस पर कर को घटाया जाता है, ऐसे कर को जिसे कर-मुक्त रखा गया है अथवा घटाया गया है अदा कर दिया गया समझा जाएगा ।

5. ऐसी आय को, जिसे इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार किसी सविदाकारी राज्य में कर लगाया जाना अपेक्षित नहीं होता है, ऐसी आय को उस सविदाकारी राज्य में अन्य आय पर लगाए जाने वाले कर की दर की संगणना करने के लिए हिसाब में लिया जाए ।

## अध्याय - V

## विशेष उपबन्ध

## अनुच्छेद 25

## सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो इस कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रकों पर समान परिस्थितियों में और समान शर्तों के अंतर्गत लागू होती हैं अथवा लागू हो सकती हैं ।
2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थान पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में आयद उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के समान कार्यों में लगे हुए उद्यमों पर समान परिस्थितियों अथवा समान शर्तों पर लगाया जाता है ।
3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें, राहतें और कटौतियां प्रदान करने को बाध्य होगा जो कानून केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध है, जो वहां के निवासी हैं ।
4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा को लागू नहीं किया जाएगा, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यमों पर समान परिस्थितियों और समान शर्तों के अधीन लागू है अथवा लागू हो सकती हैं ।
5. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद से वे कर अभिप्रेत हैं जो इस अभिसमय के विषय हैं ।



## अनुच्छेद 26

## पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यकलापों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा मुहैया किए गए उपायों के होते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है। इस दावे को कर-निर्धारण की तारीख से अथवा स्रोत पर कर के अवधारण की तारीख से, जो भी बाद में हो, दो वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी समुचित समाधान करने में समर्थ न हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अभिसमय की व्याख्या करने अथवा लागू करने के संबंध में उत्पन्न किन्हीं कठिनाइयों अथवा संदेहों को पारस्परिक सहमति द्वारा हल करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श भी कर सकते हैं, जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त पैराग्राफ के अभिप्राय से किसी सहमति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब सहमति होने में विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

## अनुच्छेद 27

## सूचना का आदान-प्रदान

1. सौंदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अथवा सौंदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो कर इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था ऐसे करों की घोषाघड़ी अथवा अपवंचन को रोकने के लिए इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना के आदान-प्रदान को अनुच्छेद-1 द्वारा प्रतिबन्धित नहीं किया जाता है । किसी सौंदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किसी सूचना को उसी रीति में गुप्त समझा जाएगा जैसा कि उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत सूचना प्राप्त की जाती है और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों §न्यायालयों तथा प्रशासनिक निकायों सहित§ को प्रकट किया जाएगा जो इस अभिसमय के अंतर्गत आने वाले करों को निर्धारण में अथवा उनकी वसूली में अथवा उनको प्रवृत्त करने अथवा उनके अभियोजन के संबंध में अथवा उस संबंध में अपीलों के निर्धारण के कार्य में अंतर्गस्त हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे । वे लोक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक की निर्णयों में सूचना को प्रकट कर सकते हैं ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी सौंदाकारी राज्य पर निम्नलिखित उत्तरदायित्व डाला जाए :

- §क§ उस अथवा दूसरे सौंदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- §ख§ ऐसी सूचना देना, जो एक अथवा दूसरे सौंदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- §ग§ ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती है जिसको प्रकट करना सरकार की नीति §आर्डर पब्लिक§ के प्रतिकूल हो ।

## अनुच्छेद 28

## राजनयिक तथा कांसुली कार्यक्ताप

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्ग्रस्त अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कांसुली अधिकारियों को दिए गए वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

## अनुच्छेद 29

## वापस अदायगियां

1. किसी संधिदाकारी राज्य में झोत पर विधारित किए गए कर को करदाता के स्वयं के द्वारा अथवा उसकी ओर से अथवा उस राज्य द्वारा, जिसका वह निवासी है, आवेदन करने पर वापस किया जाएगा, यदि ऐसा निवासी इस अभिसमय के उपबंधों के अंतर्गत उस कर की वापसी के लिए हकदार है ।
2. वापसी के लिए आवेदन उस संधिदाकारी राज्य के कानून द्वारा नियत समय-सीमा के अंतर्गत किया जाएगा जिसमें कर को विधारित किया गया है तथा उसके साथ उस संधिदाकारी राज्य का, जिसका करदाता निवासी है, एक प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करने के लिए संलग्न किया जाएगा कि वापसी की हकदारी के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी कर दी गई हैं ।
3. संधिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, पारस्परिक सहमति द्वारा इस अभिसमय के अनुच्छेद 26 के उपबंधों के अनुसरण में इस अनुच्छेद को लागू करने की पद्धति का निपटारा करेंगे ।

## अध्याय - VI

## अन्तिम उपबन्ध

## अनुच्छेद 30

## प्रवर्तन

1. यह अभिसमय अनुसमर्थित किया जाएगा और इस अनुसमर्थन के दस्तावेजों को \_\_\_\_\_ रोम \_\_\_\_\_ में यथा-सम्भव शीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा ।

2. यह अभिसमय अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख को लागू होगा और इनके उपबन्धों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :

॥क॥ भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय लागू होता है, उस वर्ष के अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी "पूर्ववर्ती वर्ष" में कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

॥ख॥ इटली में, जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय लागू होता है, उस वर्ष के अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाली किसी कर लगने योग्य अवधि में कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में ।

3. भारत सरकार और इटली सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए दिनांक 12 जनवरी, 1981 को रोम में हस्ताक्षर किया गया मौजूदा करार उस समय निष्प्रभावी हो जायेगा जब इस अभिसमय के उपबन्ध पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रभावी होंगे ।

## अनुच्छेद 31

## समाप्ति

यह अभिसमय अनिश्चितकाल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों सौंदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष की 30 जून को अथवा उस से पहले, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे सौंदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा ।

ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :-

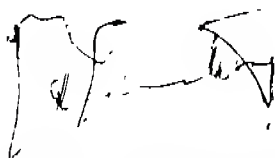
§क§ भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष में, जिसमें ऐसी सूचना दी जाती है, अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कराधान अवधि §"पूर्ववर्ती वर्ष"§ के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

§ख§ इटली में, उस कैलेण्डर वर्ष में, जिसमें ऐसी सूचना दी जाती है, अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली किसी कराधान अवधि के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

जिसके साक्ष्य में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने मौजूदा अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

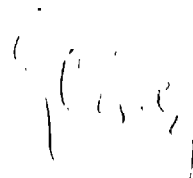
नई दिल्ली में फरवरी 19, 1993 को हिन्दी, इटैलियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं । लेकिन सन्देह के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी रहेगा ।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से



§ एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति §

इटली गणराज्य की  
सरकार की ओर से



§ क्लौडिओ विटालोन §

### प्रोटोकोल

इटली गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय हेतु प्रोटोकोल ।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए इटली गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आज सम्पन्न अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी, निम्नलिखित अतिरिक्त उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो कि उक्त अभिसमय का अभिन्न अंग होगा:

यह समझा जाता है:

§क§ कि अनुच्छेद 7, पैराग्राफ 3 के संदर्भ में पद "खर्चें जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजन के लिए उपगत किए गए हैं" का अर्थ है- वे खर्चें जो प्रत्यक्षतः स्थायी संस्थापन के कार्यकलाप और रायल्टियों, कमीशन और प्रतिपूर्ति किए गए खर्चों की वास्तविक राशि की मात्रा तक ब्याज से संबंधित है और दोनों ही मामलों में उस संबंधकारी राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार यथा-अनुमत्य हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है;

§ख§ कि अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2 के संदर्भ में "ऋण अथवा उधार" पद का अर्थ है-भारत में, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित ऋण और उधार;

§ग§ कि, अनुच्छेद 20 के संदर्भ में, इटली के बैंक में इटैलियन स्टेट रेलवे §एफ.एफ.एस.एस.ए.§ में, इटैलियन स्टेट पोस्ट उपक्रम §पी.पी.टी.टी.टी.§ में, इटैलियन विदेशी व्यापार संस्था §आई.सी.ई.टी.टी.§ में, इटैलियन पर्यटन निकाय §ई.एन.आई.टी.टी.§ और इसी प्रकार का कोई भारतीय निकाय अथवा संस्था में की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यापार को प्रदत्त पारिश्रमिक, संबंधित सरकारी सेवा के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं और परिणामतः उपर्युक्त अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं ।

सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पारस्परिक सहमति द्वारा पूर्ववर्ती सूची में अन्य सार्वजनिक निकायों अथवा संस्थाओं को भी शामिल कर लिया जाए ।

§घ§ कि अनुच्छेद 24, पैराग्राफ 4§ख§ के संदर्भ में, भारत के मामले में कर में छूट दी गई अथवा कर में कटौती की गई का अर्थ है, कोई ऐसी रकम जो किसी कराधेय वर्ष के संबंध में भारतीय कर के रूप में देय हो जाती लेकिन कराधेय आय की संगणना करने में मंजूर किसी कटौती के लिए अथवा उस वर्ष के लिए प्रदान की गई कर में छूट अथवा कटौती इस प्रकार होगी:

§i§ आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ की धारा 10§4§, 10§4क§, 10§4ख§, 10§15§§iv§, 10क,32-क ख, 80ज ज, 80जजग,80झ और 80ण जहां तक वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर की तारीख तक लागू थे और उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है अथवा उनमें इस प्रकार से केवल मामूली तौर पर संशोधन किया गया है कि उनके सामान्य रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो;

§ii§ कर से छूट देने अथवा कर की कटौती करने के संबंध में बाद में बनाया जाने वाला कोई ऐसा अन्य उपबन्ध जिस पर सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति दे दी जाती है, जो सारतः समान स्वरूप का हो, यदि इसमें इसके बाद संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उसमें केवल इस प्रकार से मामूली तौर पर संशोधन किया गया हो जिससे कि उसके सामान्य रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

§ड·§ कि, अनुच्छेद 26, पैराग्राफ 1 के संदर्भ में "राष्ट्रीय कानूनों द्वारा किए गए उपायों के होते हुए भी" पद का अर्थ यह है कि पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया समान राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं है जिसे किसी भी अवस्था में निवारक रूप से आरम्भ किया जाएगा, जब दावा करों के निर्धारण से संबंधित है जो इस अभिसमय के अनुसार नहीं हैं;

§च§ कि, अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस अभिसमय द्वारा निर्दिष्ट कर-लाभों पर मंजूरी देने की एक पृथक् प्रक्रिया पर पारस्परिक सहमति के बारे में सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों को रोका जा सकता है ।

जिनके साक्ष्य में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने मौजूदा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में फरवरी 19, 1993 को हिन्दी, इटैलियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। लेकिन सन्देह के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी रहेगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

इटली गणराज्य की  
सरकार की ओर से

(एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)

(क्लौडिओ विटालोन)

[अधिसूचना संख्या 10075 ( फा. सं. 505/2/86-वि. क. प्र.)]

एन. पी. साहनी, संयुक्त सचिव



## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1996

## (INCOME-TAX)

G.S.R. 189(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income has entered into force on 23-11-1995 after the exchange of instruments of ratification by the Contracting States in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said Convention ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India

## ANNEXURE

## CONVENTION

**BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERN-  
MENT OF THE REPUBLIC OF ITALY FOR  
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION  
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy,

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income.

Have agreed as follows :

## CHAPTER—I

## SCOPE OF THE CONVENTION

## ARTICLE 1

## PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

## ARTICLE 2

## TAXES COVERED

1. The taxes to which the Convention shall apply are :—

(a) in the case of the India :

1—the income-tax including any surcharge thereon, and 2—the surtax ;

(hereafter referred to as “Indian tax”);

(b) in the case of Italy :

1—the personal income tax ;  
2—the corporate income tax ; and  
3—the local income tax ;

even if they are collected by withholding taxes at the source.

(hereafter referred to as “Italian Tax”).

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the person Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States, shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws which are the subject of this Convention and furnish copies of relevant enactments and regulations.

## CHAPTER—II

## DEFINITIONS

## ARTICLE 3

## GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with International Law ;
- (b) the term “Italy” means the Republic of Italy including the territorial waters of Italy and airspace above them, as well as any area beyond the said territorial waters, specifically it includes the sea-bed and the sub-soil contiguous to the territory of the peninsula and the Italian islands situated beyond the territorial waters within bounds indicated by the Italian law on the exploration and the exploitation of their natural resources ;
- (c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean India or Italy, as the context requires ;
- (d) the term “tax” means Indian tax or Italian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes ;
- (e) the term “person” shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (f) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a company or a body corporate under the

taxation laws of the respective Contracting States ;

- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting States ;
- (h) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ;
- (i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State ;
- (j) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the law in force in the Contracting State ;
- (k) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative, and in the case of Italy, the Ministry of Finance ;

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

#### ARTICLE 4

##### FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of that State in accordance with the taxation laws of that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests") ;

- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode ;

- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national ;

- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

#### ARTICLE 5

##### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources ;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others ;
- (h) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders ;
- (i) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources ;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites projects or activities, if any) continue for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment.

Provided that for the purpose of this paragraph an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with or supplies plant and machinery on hire used or to be used in, the prospecting for, or extraction or production of mineral oils in the State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise. However, the provisions of sub-paragraph (a) to (e) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise ;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprise controlling controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise.

- (d) in so acting, he manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprise controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

### Chapter III

## TAXATION OF INCOME

### ARTICLE 6

#### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and right to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

### ARTICLE 7

#### BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated



therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (a) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### ARTICLE 8

##### AIR TRANSPORT

1. Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article :

- (a) interest of funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft; and

- (b) the term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

#### ARTICLE 9

##### SHIPPING

1. Income of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

3. For the purpose of this Article interest on funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. For the purpose of paragraph 1 of this Article income from the operation of ships in international traffic shall include :

- (a) profits derived from the rental on a full or bareboat basis of ships if such rental profits are incidental to the operation of ships in international traffic, and
- (b) profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

5. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

#### ARTICLE 10

##### ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

## ARTICLE 11

## DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 10 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The provisions of paragraph 2(a) would apply in respect of dividends arising out of the investment made after the date of signature of the Convention.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the dividends shall be taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

## ARTICLE 12

## INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the tax chargeable in a Contracting State on interest arising in that State and paid to a resident of the other Contracting State in respect of loans or debts shall not exceed 15 per cent of the gross amount of such interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if :

- (a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof, or
- (b) the interest is paid to any agency or instrumentality (including a financial institution) which may be agreed upon in this behalf by the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest shall be taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In

that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

### ARTICLE 13

#### ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of the person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provisions of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the royalties or fees for technical services shall be taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall

be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

### ARTICLE 14

#### CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

### ARTICLE 15

#### INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if:

- (a) he is present in that other State for a period or periods aggregating 183 days in the relevant fiscal year, or
- (b) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities but only so much of the income as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.



## ARTICLE 16

## DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. In the employment so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerning; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

## ARTICLE 17

## DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a Company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

## ARTICLE 18

## ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivision or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivision or local authorities.

## ARTICLE 19

## PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment may be taxed in both the Contracting States.

## ARTICLE 20

## GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who :

- (i) is a national of that State, or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 16, 17, 18 and 19 shall apply to remunerations and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

## ARTICLE 21

## PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, owned by the Government or non-profit organizations, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

## ARTICLE 22

## STUDENTS AND TRAINEES

1. An individual who is a resident of a Contracting State and visits the other Contracting State solely :

- (a) as a student at a university, college or other recognised educational institution in that other Contracting State, or
- (b) as a business apprentice, or

(c) for the purpose of study, research or training, as a recipient of a grant, allowance or award, from a governmental, religious, charitable, scientific or educational organisation, shall be exempt from tax in that other Contracting State :

- (i) on his remuneration and all remittances from abroad for the purposes of maintenance, education or training;

- (ii) on the grant, allowance or award; and
- (iii) in respect of remuneration for an employment in that other Contracting State for such period of time as may be necessarily required for the completion of study, research or training, as the case may be.

2. An individual who is a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for a period not exceeding one year as employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in paragraph 1 for the primary purpose of acquiring technical, professional or business experience from a person other than such enterprise or organisation shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration for an employment in that other Contracting State for such period, to the extent such remuneration does not exceed 5,000,000. Italian Lires or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

#### ARTICLE 23

##### OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention may be taxed in both the Contracting States.

#### CHAPTER IV

#### ARTICLE 24

##### METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

3. (a) The amount of Italian tax payable under the laws of Italy and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Italy which has been subjected to tax both in India and Italy, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.
- (b) For the purposes of the credit referred to in subparagraph (a) above, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income-tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.
4. (a) If a resident of Italy owns items of income which are taxable in India, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the Indian tax on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

On the contrary no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

- (b) For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this Article, where tax on business profits, dividends, interests, royalties or fees for technical services arising in a Contracting State is exempted or reduced in accordance with the taxation laws of that State, such

tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid.

5. Income which in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax in a Contracting State may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State on other income.

#### CHAPTER V

##### SPECIAL PROVISIONS

#### ARTICLE 25

##### NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprise of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

#### ARTICLE 26

##### MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.



## ARTICLE 27

## EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well to prevent fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :—

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

## ARTICLE 28

## DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

## ARTICLE 29

## REFUNDS

1. Tax withheld at source in a contracting State shall be refunded on application by or on behalf of the taxpayer or by the State of which he is a resident if such resident is entitled to a refund of that tax under the provisions of this Convention.

1040 GI/96—6

2. Application for refund shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State in which the tax has been withheld and shall be accompanied by a certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying that the conditions required for entitlement to the refund have been fulfilled.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of the Article 26 of this Convention.

## CHAPTER VI

## FINAL PROVISIONS

## ARTICLE 30

## ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect :

- (a) in India, in respect of income assessable in any "previous year" commencing on or after the first day of April of the calendar year next following the calendar year in which the Convention enters into force;
- (b) in Italy, in respect of income assessable in any taxable period commencing on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the Convention enters into force.

3. The existing Agreement between the Government of India and the Government of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Rome on 12th January, 1981 shall cease to have effect at the time when the provisions of this Convention shall be effective in accordance with the provisions of paragraph 2.

## ARTICLE 31

## TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

In such event the Convention shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income assessable for any taxable period ("previous year") commencing on or after the 1st day of April in the calendar year next following that in which such notice is given.
- (b) in Italy, in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st day of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present.

Done in duplicate at New Delhi the 19th day of February 1993, in the Hindi, Italian and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India (M. V. Chandrashekara Murthy)

For the Government of the Republic of Italy

Sd/-

(Claudio Vitalone)

### PROTOCOL

To the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect of taxes on income.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect of taxes on income, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood :

- (a) that, with reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment, and royalties, commission and interest to the extent of the actual amount of expenses reimbursed, and in both cases as admissible in accordance with the provisions of the taxation laws

of the Contracting State in which the permanent establishment is situated;

- (b) that, with reference to Article 12, paragraph 2, the expression "loans or debts" means, in the case of India, loans or debts approved in this behalf by the Government of India;
- (c) that, with reference to Article 20, the remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy, to the Italian State Railways (F.F. SS.), to the Italian State Post undertaking (P.P. T.T.), to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.), to the Italian Tourism body (E.N.I.T.), and to any corresponding Indian body or institution, are covered by the provisions concerning government service and, consequently, by paragraphs 1 and 2 of the aforesaid Article.

Other public bodies or institutions may also be included in the preceding list by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting States.

- (d) that, with reference to Article 24, paragraph 4(b), tax exempted or reduced means, in the case of India, any amount which would have been payable, in respect of a taxable year as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under :
- (i) Sections 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(15)(iv), 10A, 32AB, 80HH, 80HHC, 80-I and 80-U of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of this Convention or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character;
- (ii) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.
- (e) that, with reference to Article 26, paragraph 1, the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative to the national ordinary proceedings which

shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Convention.

- (f) that, with reference to paragraph 3 of Article 29, the provisions herein contained shall not be construed as preventing the competent authorities of the Contracting States from mutually agreeing upon a different procedure for the granting of tax benefits provided by this Convention.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at New Delhi the 19th day of February 1993, in the Hindi, Italian and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of India  
Sd/-

(M. V. Chandrashekara Murthy)

For the Government of  
the Republic of Italy

Sd/-

(Claudio Vitalone)

[Notification No. 10075/95-F. No. 505/2/  
86-FTD]

N. P. SAHNI, Jt. Secy.

